on-going dissemination/demonstration programmes of non-conventional energy sources.

(if) Village-Kolna (Chunar) has been selected under the Urjagram programme and the survey work has been completed.

(iii) Block-Narainpur has been selected under the Integrated Rural Energy Programme.

(c) Besides, the on-going dissemination programmes of biogas, improved chulha and solar thermal, which are sanctioned on year to year basis, a 10 MW wind farm project has been received from the State Govt, for financial assistance.' 10 numbers of micro hydel schemes have been recently approved as per provisions of the Small Hydro Power Development Programme of the Ministry of Non-Conventional Energy Sources.

Separate Banking and Economic Offences Division under CBI

703. SHRI SHIV PRATAP MISHRA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a separate division under CBI to deal with banking and economic offences; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA) : (a) and *(b)* A proposal to set up a separate division in the CBI to deal with banking and economic offences, is under consideration.

Resource Crunch in CBI

704. SHRI SHIV PRATAP MISHRA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that due to increasing workload, CBI is facing resource-crunch; and

(b) if so, the measures taken by Government to strengthen the organisation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA) : (a) and (b) No, Sir. Adequate additional funds are placed at the disposal of Central Bureau of Investigation as and when it is considered justifiable owing to increase in its workload.

सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पद

705. श्री अनन्त राम जायसवाल
श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हजारों पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इन रिक्त पदों का विभाग-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रश्न-गत रिक्तियां अधिक से अधिक कितने समय से रिक्त पड़ी हुई हैं;

(घ) इन रिक्तियों को किस निश्चित अवधि तक भर दिया जाएगा;

(ङ) आरक्षित रिक्तियों को भरने के क्या निदेश हैं और उनके उल्लंघन या अतिक्रमण के लिए क्या किसी दण्ड का भी प्रावधान है; और

(च) इतनी बड़ी संख्या में पदों के रिक्त पड़े रहने के कारण और परिस्थितियां क्या हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (च) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण, इन जातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियां रिक्त पड़ी हुई हैं । मंत्रालयों/विभागों द्वारा पर प्रयास किए जा रहे हैं कि इन रिक्तियों को, जहां तक संभव हो सके शीघ्र ही भर लिया जाए । वर्ष 1989 में ऐसे बाद